विचार बिन्दु

महान विचार ही कार्य रूप में परिणत होकर महान कार्य बनते हैं। –विनोबा

सरकार के दो साल, जनता का हाल बेहाल

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के दो वर्ष की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसमें प्रत्येक विभाग की उपलब्धियों के आंकड़े दिए गए और बताया गया कि विभिन्न विभागों ने राजस्थान को देश में प्रथम स्थान दिलाया है।

इस लेख का उद्देश्य मुख्यमंत्री द्वारा इस सम्मेलन में दिए गए आंकडों को चुनौती देना नहीं है, बल्कि केवल यह कि आम जनता के जीवन पर इन दो सालों में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है एवं क्या उसका जीवन पहले से बेहतर हुआ है? क्या उसके साथ अन्याय पहले से कम हुआ है? क्या सरकार अपने वे सब काम भलीभांति कर रही है जिससे आम जनता का जीवन प्रभावित होता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, अपराधों पर नियंत्रण आदि।

जहां तक आंकडों का प्रश्न है, अर्थशास्त्री एक ही प्रकार के आंकडों से अलग-अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आंकडों का प्रस्तुतीकरण अपने-अपने दृष्टिकोण से करता है और निष्कर्ष भी उसी अनुसार निकालता है। आंकडों की जादूगरी करने में आर्थिक विशेषज्ञों को महारत हासिल है। राजनीतिक दल भी इनका उपयोग अपने हित अनुसार करते हैं।

यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला देश है। यहां की जीडीपी वृद्धि की दर अन्य सभी देशों से कहीं अधिक है। भारत की कुल जीडीपी पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है। लेकिन यदि हम इसके उलट, यह देखें कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, देश के नागरिकों की आय में असमानता कितनी है, उन्हें मिलने वाली मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता की स्थिति क्या है, एवं भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, तो हम यह पाएंगे कि इन सब पैमानों पर भारत विश्व में बहुत नीचे के पायदान पर खड़ा है। इन मापदंडों पर भारत कई अफ्रीकी देशों से भी पीछे है।

अंग्रेजी में कहावत है, " Test of the pudding is in eating it". सरकार के परिप्रेक्ष्य में हम इसे देखें तो यह कहेंगे कि योजना पर कितना खर्च हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उससे राज्य की जनता कैसे प्रभावित हुई? आइए, हम कुछ क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां का विश्लेषण, इस दृष्टि से करने का प्रयास करें।

कुछ ही दिनों पहले मीडिया में प्रमुखता से यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि राज्य के केवल 9 जिलों में ही 300 से अधिक शिक्षक ऐसे विद्यालयों में पद स्थापित हैं जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि लगभग 2 करोड़ रूपया महीना व्यर्थ हो रहा है। यह राशि उस जनता से एकत्रित की जाती है जो पूरी मेहनत करके जैसे-जैसे अपने लिए दो जून रोटी का जुगाड़ करती है। दूसरी ओर, अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। क्या इसे शिक्षा विभाग की असफलता नहीं माना जाएगा? आजकल सारे आंकड़ों का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है और केवल एक क्लिक पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को पूरे प्रदेश के सारे विद्यालयों का पूरा खाका उपलब्ध हो जाता है। वहां किसी अधिकारी को इतने समय तक यह क्यों नहीं पता लग पाया कि इतनी बडी संख्या में शिक्षक बिना छात्रों के वेतन प्राप्त कर रहे हैं? जिस राज्य में पैसे की कमी को बहाने के रूप में काम में लिया जाता है, वहां दो करोड रुपए प्रति माह अर्थात लगभग 25 करोड़ रूपया साल का ऐसे लोगों को वेतन के रूप में दे देना जिनके पास कोई काम नहीं है, उसे राज्य की शासन व्यवस्था को अच्छा कैसे माना जा सकता है?

शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति वैसे ही बड़ी कमजोर है और उस पर सरकारी विद्यालयों का यह हाल किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। इसके लिए शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से लेकर राज्य स्तर के अधिकारी और शिक्षा मंत्री तक को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे?

भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसी की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चलाई जा रही है। यह दावा किया जाता है कि सभी गरीब परिवारों को इसके अंतर्गत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में लाखों रुपए तक का मुफ्त में इलाज कैशलेस उपलब्ध है। जिस प्रकार के समाचार प्रतिदिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं उससे तो यही लगता है कि यह योजना केवल कागजी सिद्ध हो रही है और वास्तविक रूप से वंचित और गरीब वर्ग को अब भी किसी न किसी कागज के अभाव में मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज उपलब्ध नहीं हो रहा है। कोई मरीज यदि एक इलाज के लिए भर्ती हो और उससे संबंधित किसी अन्य प्रकार का इलाज करना पड़ जाए तो अस्पताल उससे पैसा वसूल करते हैं। सरकार के इस दावे पर विश्वास करके कि सबको अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है, यदि कोई नागरिक इलाज कराने किसी अस्पताल में पहुंच जाए तो वहां जाकर के उसके लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होने के कारण उसे इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है।

कुछ ही दिनों पहले मीडिया में प्रमुखता से यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि राज्य के केवल 9 जिलों में ही 300 से अधिक शिक्षक ऐसे विद्यालयों में पद स्थापित हैं जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि लगभग 2 करोड़ रूपया महीना व्यर्थ हो रहा है। यह राशि उस जनता से एकत्रित की जाती है जो पूरी मेहनत करके जैसे-जैसे अपने लिए दो जून रोटी का जुगाड़ करती है। दूसरी ओर, अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं।

दुर्घटनाग्रस्त होने, अचानक बीमार होने या गंभीर अवस्था होने पर अस्पताल पहुंचाने का एकमात्र साधन एंबुलेंस है। सरकार के ही द्वारा पारित नियमों के अनुसार प्रत्येक एंबुलेंस में प्राथमिक उपचार की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जैसे मरीज के लिए लेटने की साफ, सुरक्षित व्यवस्था, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नापने की मशीन और ऑक्सीमीटर के साथ ही ऑक्सीजन सिलिंडर की व्यवस्था होना अनिवार्य है। एक समाचार पत्र के रिपोर्टर द्वारा एक वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया गया तो यह सामने आया कि जयपुर जिले की लगभग 1000 एंबुलेंस में से 800 से अधिक में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव से एक बच्चे को इलाज हेतु जयपुर के जेके लोन अस्पताल में रेफर किया गया तो ,उसकी मौत रास्ते में केवल इसलिए हो गई कि उस मासूम को एंबुलेंस में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इस बच्चे की मौत की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार होगा? सरकारी व्यवस्थाओं में घोर लापरवाही और मॉनिटरिंग के अभाव में राजस्थान के नागरिक असमय काल कवलित हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं की निरंतर पुनरावृत्ति राज्य शासन की स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था की पोल खोलती हैं।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है, बिना मॉनिटरिंग के योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार ने कुछ वर्षों पूर्व एक योजना MLA-LAD प्रारंभ की थी जिसके अंतर्गत विधायकों को प्रतिवर्ष एक निर्धारित बजट आवंटित होता था, जिसे वे स्थानीय आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा से कोई भी काम स्वीकृत कर सकते थे। कार्य किस विभाग या एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, यह तय करने का अधिकार भी संबंधित विधायक को दिया गया था। प्रारंभ में इसके अंतर्गत 40 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान था, जो अब बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो गया है। इस का मुख्य उद्देश्य यह था कि स्थानीय स्तर के अत्यावश्यक उपयोगी काम संबंधित विधायक इस राशि से करवा सकें।

कुछ समय पहले तक सुना जाता था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कामों को लिए एजेंसी तय करते समय विधायक/ सांसद कुछ धनराशि संबंधित विभाग के अधिकारियों से ले लिया करते थे, किंतु राजस्थान में जो हाल ही में स्थिति सामने आई है वह तो और भी चिंताजनक और भयावह है। एक रिपोर्टर ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया तो खींवसर के विधायक डांगा ने तो कार्य पर खर्च होने वाली राशि का 30 से 40इ तक लेने की मांग है। कल्पना ही की जा सकती है कि जिस काम की स्वीकृति के लिए विधायक 40इ राशि रिश्वत में लेगा तो, उस काम पर वास्तव में कितना खर्च होगा? ऐसे ही रिश्वत लेने की बात एक निर्दलीय और एक कांठोस के विधायक ने भी की। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे कराए गए काम अत्यंत घटिया स्तर के होंगे जो शीघ्र ही बेकार हो जाएंगे। सड़कें टूट जायेंगी, और विद्यालय की छत ध्वस्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने पद संभालते ही कहा था कि ''न मैं खाऊंगा, ना खाने दूंगा''। भाजपा विधायक की इस हरकत पर अब प्रधानमंत्री क्या कार्यवाही करते हैं, इस पर सबकी नज़र रहेगी।

आशा है, तत्काल इनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात यह है कि मीडिया में जिन विधायकों को एमएलए फंड से स्वीकृति के लिए पैसे की मांग करते हुए रिकॉर्ड पर पकड़ा गया, उनमें भाजपा के अतिरिक्त एक कांग्रेस का और एक निर्दलीय विधायक भी है।

नशे की स्थिति यह है कि पूरा शहर ही नशे के जाल में झकड़ा हुआ नजर आता है। युवा, विशेष कर नाबालिग़ बच्चे इन ड्रग्स का शिकार होकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य की राजधानी जयपुर में यह विद्यालयों के पास और विभिन्न स्थानों पर धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। जब किसी समाचार पत्र का एक रिपोर्टर यह पता कर सकता है कि कहां किस प्रकार के ड्रग्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो वहां के थानेदार या उच्च पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं होगी? जानकारी होगी अवश्य, किंतु शायद लालच में वे उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं।

शहर की सफाई, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था में गत 2 वर्ष में कोई सुधार नहीं हुआ है, अपितु स्थिति पहले से और खराब हो गई है। राज्य की राजधानी जयपुर में विभिन्न बस्तियों में गंदगी के ढेर प्रतिदिन देखे जा सकते हैं। बेतरतीब पार्किंग यथावत है और सड़कें अनधिकृत पार्किंग से ठास्त हैं। जब इंदौर गंदगी से मुक्त हो सकता है, तो जयपुर क्यों नहीं? क्या यह नहीं हो सकता कि शहर से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी चाहे वे पी डब्लू डी, पी एच ई डी, नगर निगम, राजस्व, विद्युत, ट्रैफिक विभाग के हों, सभी नगर निगम के अधीन होने चाहिएं। उन पर पूरा प्रशासनिक नियंत्रण नगर निगम का ही होना चाहिए। तब, समन्वय की समस्या नहीं रहेगी।

यदि वास्तव में मुख्यमंत्री को जनता का विश्वास प्राप्त करना है और सुशासन वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज कराना है तो उन्हें अपने कार्यकाल के शेष 3 वर्ष में केवल आंकड़ों पर ध्यान देने के बजाय ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे धरातल पर आमजन को उसका वास्तविक लाभ मिले। इसका आकलन करने हेतु स्वतंत्र, निष्पक्ष व्यक्तियों से फीडबैक लिया जाना चाहिए।

जब सरकार अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है तो आम जनता यही अपेक्षा करती है कि उसके सारे काम सरकार में बिना परेशानी के हों, जो पैसा उससे वसूल किया जाता है उसका शत प्रतिशत सदुपयोग किया जाए और जो इसमें बाधक बने उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जनता को सूचित किया जाए। ऐसा करने में प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना एवं दल के कार्यकर्ताओं का विरोध भी मुख्यमंत्री को झेलना पड़ सकता है, किंतु जनता के हित का यही रास्ता है जो उन्हें लोकप्रियता प्रदान करेगा और साथ ही जनता को राहत भी।

मुख्यमंत्री का जन्म दिवस भी संयोग से 15 दिसंबर को है, अतः उन्हें जन्मदिन की बधाई के साथ ही उनके कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा करने पर बधाई एवं उनके शेष कार्यकाल के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं। मेरी यह कामना है कि एक वर्ष बाद जब मैं ऐसा ही संपादकीय लिखूं तो शीर्षक ऐसा हो, ''सरकार के तीन साल, आम जन खुश हाल''।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

सुशासन की सेहत : मजबूत होता राजस्थान का सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र

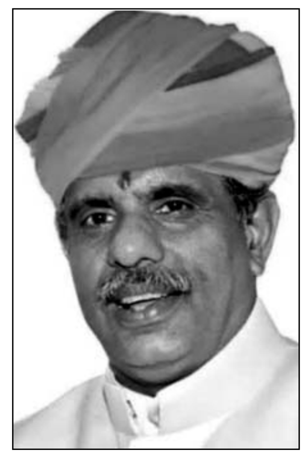

गजेन्द्र सिंह खींवसर

स्वास्थ्य तंत्र सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का सबसे प्रामाणिक पैमाना होता है। राज्य सरकार का विगत 2 वर्षों में यह प्रयास रहा है कि गरीब परिवार बिना आर्थिक चिंता के इलाज पा सके, एक गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिले और गंभीर बीमारी भी परिवार को कर्ज़ के दलदल में न धकेले।

राजस्थान ने गत दो वर्षों में इसी कसौटी पर अपने स्वास्थ्य तंत्र को नए सिरे से सुदृढ़ करने का कार्य किया है। यह परिवर्तन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट मार्गदर्शन, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और परिणामोन्मुख प्रशासनिक संस्कृति का प्रत्यक्ष परिणाम है। मुख्यमंत्री का आरंभ से ही यह दृष्टिकोण रहा है कि स्वास्थ्य योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पहुंचे। इसी सोच के अनुरूप राज्य सरकार ने निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, आयुष्मान आरोग्य, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा हर स्तर पर ठोस, मापनीय और जनजीवन को सीधे प्रभावित करने वाले कदम उठाए हैं।

राजस्थान आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जहाँ निःशुल्क दवा योजना केवल सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन का उदाहरण बन चुकी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत लगभग 1034 करोड़ रुपये से अधिक की दवाइयों की आपूर्ति कर 10 करोड़ से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया गया। मेडिकल कॉलेज स्तर से लेकर उप-स्वास्थ्य केंद्रों तक आवश्यक दवाएं, सर्जिकल और सूचर सामग्री सुनिश्चित की गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 774 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से लगभग 30 करोड़ जांचें की गईं, जिससे 8 करोड़ से अधिक मरीजों को सीधा लाभ मिला। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को न केवल आर्थिक राहत मिली, बल्कि समय पर जांच और इलाज संभव हो सका।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा विस्तार कर इसमें 132 नए पैकेज जोड़े गए। इसके अंतर्गत 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6860 करोड़ रुपये से अधिक की कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराई गई। यह योजना अब केवल राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि इन-बाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य राज्यों के लाभार्थियों को भी राजस्थान में उपचार का लाभ दे रही है। यह न केवल योजना की मजबूती दर्शाता है, बल्कि राजस्थान को विश्वसनीय स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में स्थापित करता है। पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। प्रदेश में 7 उप जिला अस्पतालो को जिला अस्पताल में उन्नयन, 61 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उप जिला अस्पतालों में उन्नयन किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को भौगोलिक दृष्टि से सुलभ बनाने के लिए 49 नए उप-स्वास्थ्य केंद्र, 6 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 379 नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रारंभ किए गए।

डायलिसिस, वेंटिलेटर, सोनोग्राफी और आईसीयू सुविधाओं के विस्तार के तहत राज्य के 195 चिकित्सा संस्थानों में 390 डायलिसिस मशीनें, 186 वेंटिलेटर और 51 सोनोग्राफी मशीनें स्थापित की गईं। इससे गंभीर रोगियों को जिला स्तर पर ही बेहतर उपचार उपलब्ध हो सका है। आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 53 पुराने 108 एंबुलेंस वाहनों के स्थान पर नए वाहन लगाए गए तथा 196 नई 108 एंबुलेंस सेवा में जोड़ी गईं। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड ट्रॉमा रिस्पॉन्स सिस्टम की पायलट शुरुआत ने दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता की क्षमता बढ़ाई।

राज्य में 18 लाख से अधिक संस्थागत प्रसव, 25 लाख से अधिक निःशुल्क जांच, 17 लाख से अधिक निःशुल्क पोषण और 12 लाख से अधिक महिलाओं को अस्पताल से घर तक निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की गई। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स में 2.33 लाख नवजातों का उपचार हुआ। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से ठास्त 594 बच्चों सहित हजारों बच्चों की सर्जरी और उपचार सुनिश्चित किया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 459 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन और 317 को राज्य स्तरीय प्रमाणन प्राप्त हुआ। नशीली दवाओं के दुरुपयोग, मिलावटखोरी और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए हजारों निरीक्षण, लाइसेंस निलंबन-रद्दीकरण और करोड़ों रुपये की जब्ती की गई।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक विस्तार हुआ।नए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से एमबीबीएस सीटों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। साथ ही पीजी और सुपर-स्पेशियलिटी सीटों का विस्तार हुआ है।

आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा को मुख्यधारा से जोड़ते हुए आयुष्मान योजना में 20 आयुष पैकेज शामिल किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर 1.69 लाख से अधिक स्थानों पर आयोजन और एक करोड़ से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी ने राजस्थान को देश में अग्रणी स्थान दिलाया।

आज राजस्थान का स्वास्थ्य तंत्र प्रतिक्रियात्मक से आगे बढ़कर पूर्व-नियोजित, तकनीक आधारित और जन केंद्रित मॉडल की ओर अठासर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह सिद्ध हुआ है कि जब राजनीतिक संकल्प स्पष्ट हो और प्रशासनिक क्रियान्वयन ईमानदार, तो स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी परिवर्तन संभव है।

स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह यात्रा केवल उपलब्धियों की सूची नहीं, बल्कि जन-विश्वास की पुनर्स्थापना की कहानी है। आने वाले वर्षों में राजस्थान न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं वाला राज्य बनेगा, बल्कि देश के लिए सुशासन आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल का उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा।

गजेन्द्र सिंह खींवसर
स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान

नियमों की अनदेखी पर 13 बाल वाहिनियों के चालान काटे, कई वाहन जब्त

दो बाल वाहिनी, एक स्कूल वेन व 10 वाहनों को शर्तो के उल्लंघन करने पर जब्त किया

पावटा, (निसं)। विराटनगर थाना पुलिस ने नियमों की अनदेखी पर 13 बाल वाहिनियों के चालान काटे। जांच के दौरान कई वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना, और वैध दस्तावेजों की अनुपस्थिति जैसे गंभीर उल्लंघन पाए गए।

विराटनगर थाना पुलिस ने नियमों की अनदेखी पर बाल वाहिनियों को जब्त किया।

पुलिस ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के तत्वाधान एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटपुतली-बहरोड के निर्देशन व तालुका विधिक सेवा सेवा समिति विराटनगर अध्यक्ष कुमार मोहन, सीबीईओ विराटनगर रामेश्वर जाट, आरटीओ भारतेंदु, विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल संयुक्त टीम का गठन कर विराटनगर थाना क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में उपयोग में ली जा रही बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद विराटनगर थाना क्षेत्र में स्कूल वाहनों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई की गई। बाल वाहिनियों पर की गई कार्यवाही में बिना फिटनेस, बिना कैमरे के संचालित जांच के दौरान लगभग 30 बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया गया। वहीं 13 बाल वाहिनियों का चालान किया गया, 1 वाहन फिटनेस नहीं होने के कारण जब्त किया गया, 1 वाहन की भौतिक स्थिति खराब होने के कारण जब्त किया गया एवं 10 वाहनों को बिना कैमरे व परमिट का उल्लंघन किया पाए जाने पर जब्त किया गया। इस अभियान में पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग को इस संयुक्त कार्यवाही ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया।

पुलिस के अनुसार क्षेत्र के कई स्कूल संचालक लंबे समय से परिवहन नियमों की अनदेखी कर रहे थे, जिससे स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ रही थी।

वही स्कूल संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे यातायात नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसके बावजूद कुछ स्कूल संचालक बेपरवाह बने रहे, जिसके चलते पुलिस ने सोमवार सुबह विशेष अभियान चलाया। विभिन्न मार्गों पर संचालित हो रही बाल वाहिनियों को रोका गया, उनकी जांच की गई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत सीज कर थाने में खड़ा करवाया गया।

■ अभियान में पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सख्त कदम उठाए

थानाधिकारी सोहनलाल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है कि यदि किसी ने भी भविष्य में नियमों की अवहेलना की तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दो दशक से मरम्मत को तरस रही है सड़क

सांभर में सिंधी व गोला बाजार की सड़क करीब दो दशक से मरम्मत को तरस रही है

सांभरझील, (निसं)। सांभर के दो महत्वपूर्ण सिंधी व गोला बाजार की सड़क करीब दो दशक से मरम्मत को तरस रही है। इन दोनों बाजारों की अनदेखी की मुख्य वजह आमजन की समझ से परे है। सिंधी बाजार की सड़क की तो जगह-जगह से कंक्रीट तक बिखर चुकी है। दो पहिया वाहन तो दूर पैदल चलना भी कठिन हो रहा है।

जानकारी के अनुसार विगत दो दशकों में करोड़ों रुपया नगर की सड़कों पर खर्च किया जा चुका है इनमें से कुछ मार्गों की सड़कें तो ऐसी है जो पहले से ही ठीक हालत में थी। लेकिन उखाड़ कर दोबारा बनाई गई जिसका कोई औचित्य नहीं था। इन सड़कों को सुधारने के लिए न तो कोई प्लान तैयार किया गया और न ही जनप्रतिनिधियों ने इसमें इंट्रेस्ट लिया। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाता है। जगह-जगह कीचड़ जमा होने से गोला बाजार के हालात भी बद्तर हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान सर्किल से लेकर साल्ट फाटक तक सड़क भी अनेक जगह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। पिछले साल पर्यटन महोत्सव के प्रारंभ होने से पहले इन गड्ढों को भरवारा गया था फिर उसके बाद दोबारा सुध नहीं ली।

■ बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, कीचड़ जमा होने से गोला बाजार के हालात भी खराब हो जाते हैं

पुरानी देवयानी रोड छोटा बाजार में काफी दूरी तक पेयजल लाइन के लिए खोदी गई सड़क आज तक नहीं बन सकी है। छोटा बाजार से बड़ा बाजार तक की सड़क की सुध केवल वर्ष में एक बार यानी धूलंडी के अवसर पर ली जाती है वह भी केवल गड्ढों को भरने तक सीमित रहती है। इन मुद्दों को जिम्मेदार पार्षद बोर्ड की बैठक में उठाना तक भूल जाते हैं। यहां की बोर्ड की मीटिंग भी अब तक जितनी बार हुई है करीब करीब औपचारिकता पूर्ण सिद्ध हुई है।

राशिफल मंगलवार 16 दिसम्बर, 2025

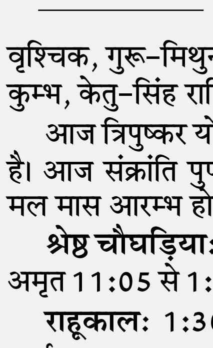

पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, स्वाती नक्षत्र दिन 2:10 तक, अतिगंड योग दिन 1:23 तक, कौलव करण दिन 10:39 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-तुला, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज त्रिपुष्कर योग दिन 2:10 से रात्रि 11:58 तक है। आज संक्रांति पुण्यकाल पूर्वान्ह में है। आज से धनु मल मास आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:47 से 11:05 तक, लाभ-अमृत 11:05 से 1:40 तक, शुभ 2:57 से 4:14 तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:13, सूर्यास्त 5:32 तक

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। शुभ कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कर्क
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिके वार्तो के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।